नेसर अहमद और अन्य

बनाम

झारखंड राज्य और अन्य

रिट याचिका (सिविल) नंबर 2010 **का** 59

फरवरी 25, 2014

[सुरिंदर सिंह निज्जर एवं ए. के. सिकरी जस्टिस]

नियुक्ति-झारखंड राज्य में प्रशिक्षित शिक्षक - सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिकाएं दायर करना-प्रत्यर्थी-प्राधिकरणों को सरकारी स्कूलों में वरिष्ठता के क्रम में उन्हें सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त करने के लिए निर्देश देने की मांग करना, चाहे उनकी उम्र अधिक हो, निर्णय के संदर्भ में

बिहार राज्य में राम विनय कुमार का मामला-आयोजितः झारखंड राज्य ने सहायक/प्राथमिक शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए अपने स्वयं के नियम बनाए हैं - इसके अलावा, उच्च न्यायालय के आदेश के संदर्भ में, नियमों में संशोधन किया गया और भर्ती नियमों का सावधानीपूर्वक पालन करके नियुक्तियां की गईं-ई इसलिए, याचिकाकर्ताओं को बिहार में अपने समकक्षों के साथ अपने मामले की तुलना करने की अनुमति नहीं होगी-ऐसी परिस्थितियों में, न्यायालय अनुच्छेद के तहत दायर याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं को कोई राहत देने के लिए इच्छुक नहीं होगा। संविधान की धारा 32, विशेष रूप से, जब यह पाया जाता है कि प्रत्यर्थी/झारखंड राज्य ने अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए वैधानिक भर्ती नियमों के अनुरूप कदम उठाए हैं।

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद। 32 और 309|

तत्काल रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया और इस प्रकार उन्हें 'प्रशिक्षित शिक्षक' कहा गया, उन्होंने उत्तरदाताओं को निर्देश देने का अनुरोध किया। 1 से 3 तक, अन्य बातों के साथ-साथ, उन्हें और इसी तरह की परिस्थितियों में प्रशिक्षित शिक्षकों को झारखंड राज्य के सरकारी स्कूलों में वरिष्ठता के क्रम में सहायक शिक्षकों के रूप में नियुक्त करना, चाहे उनकी आयु अधिक हो। उन्होंने दावा किया कि वे राम विनय कुमार और अन्य के मामले में तय की गई रिट याचिका में पटना उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार नियुक्तियों के हकदार थे|

<u>निर्णय</u>

<u>ए. के. सिकरी, जे.</u>

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर इन तीन रिट याचिकाओं में सभी याचिकाकर्ता समान रूप से स्थित हैं। आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उन्होंने 'प्रशिक्षित शिक्षकों' का उपाधि प्राप्त कर लिया है। वे प्रतिवादी झारखंड राज्य द्वारा संचालित स्कूलों में सहायक शिक्षकों के रूप में नियुक्ति चाहते हैं। समान परिस्थिति में कई शिक्षकों द्वारा अभियोग लगाने और समान राहत की मांग करने के लिए कुछ अंतर्वर्ती आवेदन दायर किए गए। यही कारण है कि इन याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई की गई ।

2. रिट याचिका (सिविल) नं। 2010 का 173 में वर्णित सटीक प्रार्थना, इन याचिकाकर्ताओं द्वारा स्थापित मामले की प्रकृति और राहत की एक झलक देगा जिसके लिए ये याचिकाकर्ता प्रार्थना करते हैं । यह प्रार्थना इस प्रकार हैः

"इसलिए, यह सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि माननीय कृपया प्रसन्न होंः

i) प्रत्यार्थीयों को विशेष रूप से प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 को रिट,आदेश या निर्देश जारी करें, ,याचिकाकर्ताओं और समान रूप से योग्य प्रशिक्षित शिक्षकों को वरिष्ठता के आधार पर नियुक्त करने के लिए।

ii) प्रत्यर्थियों और विशेष रूप से झारखंड राज्य (प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3) को निर्देश देते हुए एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें और सहायक शिक्षकों के स्वीकृत रिक्त पदों पर झारखंड राज्य में उपलब्ध प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति करके झारखंड राज्य के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार की रक्षा करे ।

iii) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और न्याय के हित में ऐसे अन्य या आदेश पारित करना जो यह माननीय न्यायालय उचित और उचित समझे।

जिस पृष्ठभूमि में ये याचिकाएं दायर की गई हैं, वह कुछ हद तक विस्तृत है एवं उतार चढ़ाव भरा है , जिसमें पिछले मुकदमे के लाभ से भरा हुआ है , जिसके बारे में याचिकाकर्ता मांग कर रहे हैं ।

हालांकि, हम इन घटनाओं को यथासंभव सरल तरीके से पार करने का प्रयास करेंगे ।

3. जैसा कि सभी जानते हैं, झारखंड राज्य की स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी। इससे पहले यह बिहार राज्य का हिस्सा था। ये सभी याचिकाकर्ता अविभाजित बिहार विंटेज के हैं. वे दावा करते हैं कि वे योग्य और प्रशिक्षित शिक्षक हैं जिन्होंने आवश्यक योग्यता और आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त किया है और इस प्रकार इस विषय पर मौजूदा नियमों के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में प्राथमिक शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए विचार करने के योग्य हो गए हैं। हालांकि, बिहार सरकार द्वारा सहायक शिक्षकों के 25,000 पदों को भरने के लिए 6.10.1991 को जारी एक विज्ञापन के आधार पर, जब सरकार कानूनी रूप से केवल प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति करने के लिए बाध्य थी, तब भी राज्य ने उक्त भर्ती प्रक्रिया में की गई 19,272 सहायक शिक्षकों की कुल नियुक्तियों में से 17,281 अप्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती की। इस चयन को कुछ व्यक्तियों द्वारा पटना के उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करके चुनौती दी गई थी, जिसका निर्णय 26.9.1996 को लिया गया था। उच्च न्यायालय ने पहले से की गई नियुक्तियों को रद्द नहीं किया, हालांकि साथ ही यह भी माना कि राज्य किसी व्यक्ति को अपने आवेदन को किसी विशेष जिले तक सीमित रखने के लिए मजबूर नहीं करेगा । इस आदेश के खिलाफ, विशेष अनुमति याचिका सं 1996 का 23187 इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

उन कार्यवाहियों में शिक्षा उपाधीक्षक, बिहार सरकार द्वारा दिनांक 14.8.1997 को एक शपथपत्र दाखिल किया गया था जिसमें मौजूदा रिक्तियों के विरुद्ध प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्त करने पर सहमति व्यक्त की गई थी । उक्त शपथपत्र में किए गए कथन को ध्यान में रखते हुए, एसएलपी का निपटान दिनांक 5.9.1997 के आदेश द्वारा किया गया था। इस मामले को के रूप में जाना जाता है *राम विनय कुमार और अन्य* "

v. " *बिहार राज्य और अन्य.* " **(1998) 9 एससीसी 227** । सहायक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के संबंध में इस न्यायालय द्वारा दिए गए सटीक निर्देश निम्नलिखित हैं:

> (i) आयोग इन रिक्त पदों की नियुक्ति के उद्देश्य से उन आवेदकों के मध्य जिन्होंने अपना आवेदन जमा किया है, विशेष चयन प्रक्रिया संचालित करेगा।
>
> (ii) चयन सरकारी/निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों से प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण/योग्यता रखने वाले आवेदकों तक सीमित होगा।
>
> (iii) चयन प्रारंभिक परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा आयोजित करके किया जाएगा।
>
> (iv)यदि ऐसे विशेष चयन में नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या उन पदों की संख्या से अधिक है जिनके लिए भर्ती दिनांक 6.10.1991 के विज्ञापन के आधार पर की जानी थी, नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाए गए उम्मीदवारों की अधिशेष संख्या बाद के चयन के आधार पर भरे जाने वाले पदों के खिलाफ उचित होगी।

(v)इन निर्देशों के अनुसरण में किया जाने वाला विशेष चयन आयोग द्वारा 31.1.1997 द्वारा पूरा किया जाएगा।

4. संक्षेप में, निर्देश उन आवेदकों में से अधूरे पदों को भरने के लिए एक विशेष चयन करने का था, जिन्होंने पहले ही जारी विज्ञापन के अनुसार अपने आवेदन जमा कर दिए थे और यह उन आवेदकों तक सीमित था जिनके पास सरकारी/निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान i.e. से प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण/योग्यता थी। याचिकाकर्ताओं के अनुसार 30.9.1993 को 2,09,981 के कुल पद के मुकाबले लगभग 45,000 रिक्तियां थीं, एवं कार्यरत शिक्षकों की संख्या 1,54,751 थी । इसके अलावा, अगले तीन सालों में लगभग 18,431 शिक्षकों के सेवानिवृत होने की उम्मीद थी। इसलिए, अनुमानित रिक्तियां लगभग 63,000 थीं। बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के संदर्भ में झारखंड राज्य के निर्माण पर, आनुपातिक रिक्तियां i.e. एक तिहाई झारखंड राज्य के हिस्से में आई, जिसका अर्थ है कि इस राज्य के निर्माण की तारीख के समय 21,000 रिक्तियां उपलब्ध थीं।

5. याचिकाकर्ताओं द्वारा कहा गया है कि राम विनय कुमार के मामले में दिए गए निर्देशों की तारीख से लगभग 7 वर्षों तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।

इसने प्रशिक्षित शिक्षकों के कुछ वर्गों को कई रिट याचिकाओं के माध्यम से पटना उच्च न्यायालय का रुख करने के लिए मजबूर किया । इन सभी रिट याचिकाओं की सुनवाई प्रमुख मामले के साथ की गई जिसे *नंद किशोर ओझा एंड ओआरएस* वी. " *बिहार राज्य और अन्य.* " **(सीडब्ल्यूजेसी 13246/2003)** के रूप में जाना जाता है। इन रिट याचिकाओं को पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 1.7.2004 के फैसले के माध्यम से अनुमति दी गई थी। उक्त निर्णय में यह था *इंटर अलिया* नोट किया कि कई खाली रिक्तियां थीं जिनकी वजह से प्राथमिक विद्यालय खाली पड़े थे। उच्च न्यायालय ने राम विनय कुमार के मामले में इस न्यायालय के निर्णय को लागू नहीं करने में बिहार सरकार की ओर से निष्क्रियता की निंदा की जिससे एक युवा पीढ़ी को बुनियादी शिक्षा के अधिकार से वंचित करने में मानवाधिकार की समस्या पैदा हो रही है। उच्च न्यायालय के अनुसार, समाधान सरल था अर्थात् राम विनय कुमार के मामले में इस अदालत के फैसले का पालन करने के लिए जहां से परिस्थितियों को छोड़ दिया गया है। उच्च न्यायालय ने पहले से ही ऊपर बताए गए तरीके से मौजूदा रिक्तियों की संख्या की भी गणना की। इस आधार पर *राम विनय कुमार* के मामले में इस अदालत के आदेश के अनुसार चयन प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया गया था।

6. बिहार राज्य ने इस अदालत में विशेष अनुमति याचिका दायर करके उच्च न्यायालय के उपरोक्त फैसले को चुनौती दी।

हालांकि, इसके बाद बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के आयुक्त-सह-सचिव द्वारा दिनांक 18.1.2006 को उन विशेष अवकाश याचिकाओं को वापस लेने के लिए एक आवेदन के साथ हलफनामा दायर किया गया था। शपथ पत्र में एक वचन दिया गया था कि बिहार राज्य में केवल प्रशिक्षित शिक्षकों को सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके अलावा इस कारण से कि बिहार राज्य में उपलब्ध शिक्षकों की संख्या उपलब्ध स्वीकृत पद से कम थी और चयन के लिए किसी परीक्षा की आवश्यकता नहीं थी। इस हलफनामे के आधार पर, दिनांक 23.1.2006 के आदेश पारित किए गए थे, जिसमें सरकार को विशेष अवकाश याचिकाओं को वापस लेने की अनुमति दी गई थी।

7. जब उक्त हलफनामे में दिए गए वचन को इसके तुरंत बाद लागू नहीं किया गया, तो कुछ लोगों ने अवमानना याचिका नं 2006 का 207 इस न्यायालय में जिसे बिहार राज्य को अपने उपक्रम को लागू करने के निर्देश के साथ दिनांक 19.3.2007 के आदेशों द्वारा निपटाया गया था।

उक्त आदेश का परिचालन भाग इस प्रकार हैः

> दिनांक 7.2.2007 के उत्तर में उक्त हलफनामे के पैराग्राफ 17 में यह कहा गया है कि नियुक्ति में प्रशिक्षित शिक्षकों को प्राथमिकता दी गई है और केवल तभी जब प्रशिक्षित शिक्षक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं,

अप्रशिक्षित शिक्षकों के मामले पर पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संबंधित द्वारा विचार किया जाता है, , और इस संबंध में बिहार राज्य और अन्य प्रत्यर्थी उच्च न्यायालय और इस न्यायालय के आदेशों का पालन कर रहे हैं। याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 7.2.2007 के हलफनामे में बिहार राज्य द्वारा दिए गए बयानों पर आपत्ति जताते हुए एक प्रत्युत्तर भी दायर किया गया है।

अब दिए गए इस स्पष्ट कथन को ध्यान में रखते हुए कि नियुक्ति में प्रशिक्षित शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी और दिनांक 7.2.2007 के उपरोक्त शपथ पत्र के पैराग्राफ 19 से 222 में दिए गए स्पष्टीकरण को देखते हुए, हम बिहार राज्य को निर्देश देते हैं कि वह पहले बिहार राज्य द्वारा दिए गए वचन को लागू करे और अब भी 7.2.2007 के वर्तमान शपथ पत्र द्वारा प्राथमिकता के आधार पर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति करके इसे अक्षरशः लागू करे।

अवमानना याचिका का निपटान तदनुसार किया जाता है।

8. तब तक इस उपक्रम का पालन नहीं किया गया जिसके कारण एक और अवमानना याचिका दायर की गई। 2007 का 297 शीर्षक *नंद किशोर ओझा* वी. " *अंजनी कुमार सिंह* जिसमें दिनांक 9.12.2009 को निम्नलिखित अंतरिम आदेश पारित किए गए थे।

तदनुसार, अवमानना का नियम जारी किए बिना, हम निर्देश देते हैं कि दिसंबर, 2003 में प्रकाशित विज्ञापन में उपलब्ध 34,540 रिक्तियों को वरिष्ठता के क्रम में उपलब्ध प्रशिक्षित शिक्षकों में से भरा जाए। जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह एक बार के आधार पर किया जाना है और इसे नियमित अभ्यास के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।

अवमानना याचिका को छह सप्ताह की और अवधि के लिए स्थगित कर दिया जाए ताकि राज्य सरकार इस आदेश को लागू कर सके और याचिकाकर्ता और संबंधित अधिकारी के बीच हुई चर्चा के परिणाम के बारे में अगली तारीख को एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके।

9. इसके बाद, बिहार राज्य ने अपने उपक्रम के संदर्भ में सहायक शिक्षकों के रिक्त पदों को भरा, जिससे वर्ष 1991 में दिए गए विज्ञापन के अनुसार पहले आवेदन करने वाले प्रशिक्षित शिक्षकों में से भर्ती की गई, इस बीच कई लोग ज़्यादा उम्र के हो गए थे तो उनके मामलों में उम्र में छूट दी गई थी.

10. ऊपर जो बताया गया है वह बिहार राज्य में मुकदमेबाजी का इतिहास है।

जहां तक झारखंड राज्य का संबंध है (इसमें प्रत्यर्थी) जैसा कि पहले ही ऊपर बताया गया है, लगभग 21,000 रिक्त पदों को इस राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया था। प्रत्यर्थी ने वर्ष 2002 में केवल 5 वर्ष की आयु में छूट देकर इन रिक्तियों का विज्ञापन किया था। इस वजह से याचिकाकर्ताओं की जिस श्रेणी में कई प्रशिक्षित शिक्षक शामिल हैं, उन्हें अधिक उम्र होने के कारण सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सका। इस पृष्ठभूमि में याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि वे इस न्यायालय के *राम विनय कुमार* के फैसले का लाभ उठाने के हकदार हैं, जो झारखंड राज्य के निर्माण से बहुत पहले दिया गया था और पूर्ववर्ती एकीकृत बिहार पर लागू होता था और इस फैसले को उनके मामले में लागू किया जाना चाहिए और जैसा कि बिहार राज्य में प्रशिक्षित शिक्षकों के साथ ऊपर बताए गए तरीके से हुआ है। हम इंगित कर सकते हैं

इस स्तर पर कि प्रत्यर्थी राज्य केवल प्रशिक्षित शिक्षकों में से नियुक्ति कर रहा है। हालाँकि, समस्या इसलिए पैदा हुई है क्योंकि ये याचिकाकर्ता उम्र से ज़्यादा हो गए हैं और उम्र में पूरी छूट चाहते हैं। इसे संक्षेप में कहने के लिए, वे अपने समकक्ष बिहार राज्य के साथ समानता का दावा कर रहे हैं और यह कहते हुए कि जब उन शिक्षकों को आयु में छूट देकर नियुक्त किया गया था, तो याचिकाकर्ताओं को उसी व्यवहार से वंचित करने का कोई कारण नहीं है जो अन्यथा भेदभावपूर्ण और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा ।

11. याचिकाकर्ताओं ने बताया है कि प्रतिवादी राज्य ने फैसले को लागू करने के लिए वर्ष 2001 में एक समिति का गठन किया था और यहां तक कि उक्त समिति ने दिनांक 31.5.2001 की अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि झारखंड राज्य में सभी रिक्तियों को दो महीने के भीतर प्रशिक्षित शिक्षकों से भरा जाए। उक्त सिफारिश का ऑपरेटिव हिस्सा इस प्रकार हैः

> चूंकि सरकार ने अपने स्तर पर हजारों लोगों को शिक्षक प्रशिक्षण दिया है और प्रशिक्षित शिक्षकों को दो दशकों से उम्मीद थी कि उन्हें शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। यह पूरी तरह से अनुचित और अमानवीय है कि सरकार अप्रशिक्षित व्यक्तियों की नियुक्ति करती है और इस तरह प्रशिक्षित शिक्षकों का भविष्य बर्बाद हो जाता है। इसलिए, यहां समिति ने सिफारिश की है कि झारखंड राज्य में सभी रिक्तियों को 2 महीने के भीतर प्रशिक्षित शिक्षकों के साथ पूरा किया जाए। अगर

प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक है, फिर रिक्तियों को प्रशिक्षित शिक्षकों की वरिष्ठता के आधार पर यानी उनके प्रशिक्षण प्राप्त करने के क्रम में पूरा किया जाना चाहिए। इसके बाद,बेरोजगार प्रशिक्षित शिक्षक को बाद की रिक्तियों के लिए उन्हें नियुक्त किया जाए। नियुक्ति प्रक्रिया में आयु सीमा के नियम को कम किया जाना चाहिए क्योंकि दो दशकों से प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने बिना किसी गलती के अपनी आयु सीमा को पार कर लिया है। अन्य अप्रशिक्षित व्यक्तियों को सभी प्रशिक्षित शिक्षकों को नियोजित करने के बाद ही नियुक्त किया जा सकता है। "" "सरकार को भविष्य के लिए नीतिगत निर्णय लेना चाहिए यदि उसे आयोग द्वारा चुने जाने के बाद व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति करनी है।" "" हालांकि, समिति का मानना है कि प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति से राज्य के खजाने पर बोझ नहीं पड़ेगा, जबकि वेतन पर चुने जाने के बाद व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना एक उचित पाठ्यक्रम नहीं कहा जा सकता है भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय और विशेषज्ञ समिति ने भी प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्त करने का निर्देश दिया है।

12. याचिकाकर्ता की उपरोक्त दलीलें पहली बार में आकर्षक लग सकती हैं।

आखिरकार, एकीकृत बिहार के लिए राम विनय कुमार के मामले में फैसला इस अदालत ने प्रतिपादित किया। यह निर्णय, "राज्य के दो भागों में विभाजित होने के बाद, बिहार राज्य में लागू किया गया है, इस तथ्य के बावजूद कि बिहार राज्य में उन प्रशिक्षित शिक्षकों की उम्र अधिक हो गई थी, उन्हें नियुक्तियां दी गई हैं " " इसलिए, याचिकाकर्ताओं के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जा सकता था, जो समान रूप से स्थित हैं और भाग्य की विचित्रता से झारखंड राज्य के निवासी/अधिवास बन गए।

हालांकि, ये अवलोकन तब मान्य होंगे जब हम सिक्के का केवल एक पक्ष देखेंगे। झारखंड राज्य में इसके निर्माण के बाद हुए विकास पर ध्यान देना भी उतना ही आवश्यक है। यह पता लगाने के लिए कि क्या वे घटनाएं किसी भी तरह से स्थिति को बदल देंगी जिससे यह एक अलग मामला बन जाएगा।

13. राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री अमरेंद्र शरण ने कहा कि प्रतिवादी राज्य के निर्माण के बाद, इसने झारखंड प्राथमिक विद्यालय नियुक्ति नियम, 2002 (संक्षेप में नियम 2002) के रूप में अपने नियम बनाए। ये नियम, अन्य बातों के साथ-साथ, शिक्षक पात्रता परीक्षा का निर्धारण किया और इस परीक्षा को पास करना नियुक्ति के लिए एक प्रमुख शर्त है । उक्त नियमों के नियम 4 में शिक्षकों की चयन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में आयोजित होने वाली परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम और महत्तम आयु सीमा प्रदान की गई है। लेकिन उक्त नियम द्वारा इस आशय की रियायत दी गई थी कि पहली परीक्षा आयोजित करने के लिए महत्तम आयु पर ऐसी कोई सीमा नहीं होगी। "" "यह इस आधार पर था कि कई वर्षों से, कोई परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी या चयन नहीं किया गया था और जिन सभी लोगों ने शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त किया था, उन्हें पहली परीक्षा में बैठने का अवसर मिलना चाहिए।" इसका उद्देश्य एक बार की रियायत देना था. इसका मतलब यह था कि एक व्यक्ति जो चुने जाने या नियुक्त

होने के छह महीने के भीतर सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेगा, वह भी परीक्षा में उपस्थित हो सकता है। इस नियम का स्पष्ट उद्देश्य यहां याचिकाकर्ताओं जैसे व्यक्तियों को लाभ देना था। नियम 8 में यह प्रावधान किया गया है कि चयन के लिए लिखित परीक्षा के लिए ज्ञान का स्तर मध्य स्तर की परीक्षा होगी।

14. राज्य द्वारा उठाए गए इस कदम के बावजूद, कानूनी घटनाओं को पूरी तरह से कठिन रास्ता अपनाना था। "" " ऐसा हुआ कि उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा के गैर-निर्धारण और मध्यम स्तर के शैक्षणिक मानक पर ज्ञान को तय करने को W.P.(ग) संख्या 2002 का 5170 और W.P. (ग) संख्या 2002 का 6135 में उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी।"" इन रिट याचिकाओं को अनुमति दी गई और उच्च न्यायालय ने लिखित परीक्षा आयोजित करने के लिए मानक के रूप में ऊपरी आयु सीमा और मध्यम स्तर के निर्धारण के संबंध में दी गई बेलगाम रियायतों को रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय ने इन प्रावधानों को इस आधार पर अमान्य घोषित कर दिया ऊपरी आयु सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है और उम्मीदवारों के लिए मध्य स्तर के परीक्षा ज्ञान का निर्धारण मनमाना है, आलोचनात्मक सोच की कमी से पीड़ित है और वांछित परिणाम से संबंधित किसी भी प्रासंगिक मानदंड पर आधारित नहीं है। इस प्रकार उच्च न्यायालय ने उन दोनों प्रावधानों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन

पाया, हालांकि उक्त अनुच्छेद का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया था। अदालत ने यह भी घोषणा की कि उक्त दो नियम जनहित के के प्रतिकूल थीं। आगे की चुनौती के अभाव में, डिवीजन बेंच का यह निर्णय अंतिम हो गया। इसके बाद विधानमंडल ने नियम 4 (डी) और नियम 8 (डी) में संशोधन किया। संशोधित नियमों में कम और ऊपरी आयु सीमा प्रदान की गई है और पहली परीक्षा के लिए आयु में पांच साल की छूट दी गई है। नियम 8 (डी) द्वारा, इसने प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा की परीक्षा मानक को बढ़ाया। अगस्त 2002 में, इन संशोधित नियमों के आधार पर भर्ती करने के लिए पहला विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके बाद पूरक/दूसरा विज्ञापन दिनांक 21.4.2003 जारी किया गया था। यहां तक कि संशोधित नियम 4 (डी) और 8 (डी) कई रिट याचिकाओं में चुनौती दी गई थी, जो झारखंड उच्च न्यायालय में डब्ल्यू. पी. (C) संख्या 2003 का 2566 शीर्षक *झारखंड राजे बेरोजगर प्राथमिक प्रतिष्ठित शिक्षक संघ और अन्य* "बनाम " *झारखंड राज्य और अन्य* में मुख्य मामले के साथ दायर की गई थी।

उस रिट याचिका में मांगी गई राहतें निम्नलिखित थीं:

(i) नियम 4 (डी) को रद्द करने के लिए और 8 (डी) झारखंड प्राथमिक विद्यालय नियुक्ति नियम 2002 और 2003 के संशोधित नियमों के अनुसार अधिसूचना दिनांक 1.7.2002 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है और 6.3.2003 के माध्यम से अधिसूचना (जैसा कि रिट आवेदन के अनुलग्नक 1 और 2 में निहित है)

(ii) प्रत्यर्थीयो को मैट्रिक और उसके समकक्ष मानक की परीक्षा/चयन परीक्षा देकर

प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक का चयन करने का निर्देश देना ।

(iii) प्रत्यर्थीयों द्वारा सभी प्रशिक्षित शिक्षकों को उचित आयु तक रोजगार का अवसर और राज्य सरकार द्वारा उचित सीमा तक आयु में छूट देकर प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के रूप में उनकी नियुक्ति के लिए ।

(iv) प्रशिक्षित शिक्षक उम्मीदवारों की श्रेणी से प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक अवसर की सीमा को हटाने के लिए।

(v) किसी भी अन्य उपयुक्त राहत (ओं) के लिए जिसके लिए याचिकाकर्ता कानून और समानता में हकदार पाए जाते हैं।

15. . संक्षेप में याचिकाकर्ताओं ने संशोधित नियम 4 (डी) और नियम 8 (डी) को चुनौती दी, यह . दावा करते हुए कि ये प्रावधान न केवल असंवैधानिक थे, बल्कि पहले के फैसले में दिए गए निर्देशों का उल्लंघन करते थे । यह विशेष रूप से अनुरोध किया गया था कि प्रशिक्षित शिक्षक की नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा नहीं हो सकती । हालांकि आवेदन केवल प्रशिक्षित शिक्षकों से आमंत्रित किए गए थे, लेकिन उम्र में छूट केवल 5 वर्ष तक दी गई थी। इसे मनमाना, दुर्भावनापूर्ण और जनहित विरोधी बता कर चुनौती दी गई थी। इस रिट याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.5.2003 के अंतरिम आदेश पारित किए गए थे, जिसमें याचिकाकर्ताओं को परीक्षा जो 27.5.2003 को आयोजित होने वाली थी, में उपस्थित होने की अनुमति दी गई थी।

16. दिलचस्प बात यह है कि एक पीआईएल भी W.P. (पी. आई. एल.) संख्या 2003 का 2769 के रूप में दायर की गई थी। जिसमें याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि आयु में छूट या अन्यथा के संदर्भ में इन व्यक्तियों को कोई रियायत देने की आवश्यकता नहीं थी और भर्ती मौजूदा नियमों के अनुसार सख्ती से की जानी चाहिए।

17. इन सभी रिट याचिकाओं को एक साथ सुना गया और दिनांक 29.9.2003 के आदेश पारित करके उनका निपटारा किया गया। उक्त निर्णय में राज्य लोक सेवा आयोग की संरचना के संबंध में विभिन्न अन्य मुद्दों को भी देखा गया और उन पर विचार किया गया। हम उन पहलुओं पर चर्चा से बच रहे हैं क्योंकि यह हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं है। जहां तक कुछ प्रशिक्षित शिक्षकों और उनके संघों द्वारा दायर रिट याचिकाओं का संबंध है (वर्तमान याचिकाकर्ता किस श्रेणी में आते हैं और इनमें से अधिकांश याचिकाकर्ता उन रिट याचिकाओं के पक्षकार थे) उन्हें उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ खारिज कर दिया गया थाः

एक रिट याचिका में, इस अदालत ने एक निर्देश जारी किया कि उस रिट याचिका में तीन रिट याचिकाकर्ताओं को अस्थायी रूप से परीक्षा देने या परीक्षा लिखने की अनुमति दी जाएगी, भले ही वे रिट याचिका के परिणाम के अधीन आयु की आवश्यकता या आयु योग्यता को पूरा नहीं करते हों। "" "ऐसा प्रतीत होता है कि उस आदेश के बल पर कुछ अनियंत्रित तत्वों ने कुछ अधिकारियों या अधिकारियों को परीक्षा में बैठने के लिए हॉल टिकट जारी करने के लिए मजबूर किया, भले ही वे अधिक उम्र के थे और डिवीजन बेंच के पहले के फैसले के अनुसार जारी संशोधित नियम के अनुसार योग्य नहीं थे।" "" यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन लोगों के पास नियमों के संशोधित नियम 4 (डी) के अनुसार अपेक्षित आयु योग्यता नहीं थी, भले ही उन्होंने परीक्षाएं लिख दी हों, आयोग द्वारा या सरकार की उपस्थिति में उन लोगों की सिफारिश, चयन या नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा जिनके पास अपेक्षित योग्यता या आयु योग्यता नहीं थी, चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया से संबंधित सभी लोगों द्वारा उपेक्षा की जाएगी।

परिणामस्वरूप, W.P. (पी. आई. एल.) संख्या 2003 का 2769 के अलावा रिट याचिकाएं खारिज कर दी गईं हैं। W.P. (पी. आई. एल.) संख्या 2003 का 2769 झारखंड राज्य और राज्य लोक सेवा आयोग को झारखंड लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियम, 2000 द्वारा परिकल्पित पूर्ण राज्य लोक सेवा आयोग के अस्तित्व में आने तक अनुशंसा प्रक्रिया के साथ आगे नहीं बढ़ने के निर्देशों के साथ आंशिक रूप से अनुमत है। यह स्पष्ट किया जाता है कि अब तक उठाए गए कदमों और आयोजित परीक्षाओं को वैध माना जाएगा।

18. इस प्रकार उच्च न्यायालय ने कुल आयु छूट का लाभ देने से इनकार कर दिया, लेकिन इसे 5 वर्ष तक सीमित कर दिया, जैसा कि नियम में परिकल्पना की गई है। उस फैसले को कोई और चुनौती नहीं दी गई जिससे इसे अंतिम रूप मिल सके। नियम, 2002 के अनुसार नियुक्तियां की गई थीं। इसके बाद वर्ष 2008 में एक और विज्ञापन जारी किया गया और इसके आधार पर आगे नियुक्तियां की गईं|

19. उपरोक्त से, झारखंड राज्य में प्रचलित स्थिति को संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता हैः

(i) झारखंड राज्य के गठन के बाद इसने सहायक/प्राथमिक शिक्षकों के पद पर भर्ती के लिए अपने स्वयं के नियम बनाए हैं।

(ii) इन नियमों के अनुसार नियुक्ति केवल प्रशिक्षित शिक्षकों के बीच से की जानी है.

(iii) "अब तक की गई भर्ती प्रक्रियाओं में, राज्य ने नियमों के अनुसार सख्ती से नियुक्तियां की हैं और प्रशिक्षित शिक्षकों में से उचित चयन प्रक्रिया का पालन किया है।"

(iv) शुरू में बनाए गए नियमों में, एक बार की आयु में छूट इस प्रावधान के साथ प्रदान की गई थी कि कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं होगी। हालांकि, उस नियम को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी और उच्च न्यायालय ने उक्त नियम को असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया था। उक्त निर्णय नियमों में निहित निर्देशों का पालन करते हुए संशोधन किया गया था और संशोधित

नियमों में 5 साल तक की छूट का प्रावधान है।

जब वर्ष 2002-2003 में विज्ञापन जारी करके चयन प्रक्रिया शुरू की गई तो इन शिक्षकों (अर्थात् याचिकाकर्ताओं) ने अपने संघों आदि के माध्यम के द्वारा केवल 5 वर्ष की आयु तक छूट के बजाय पूर्ण आयु छूट का दावा करने वाली रिट याचिकाएं दायर की गईं। तथापि, इन रिट याचिकाओं को उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29.9.2003 के निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया था। इस फैसले को भी अंतिम रूप मिल गया है।

20. इस परिदृश्य में याचिकाकर्ताओं को कोई राहत देना मुश्किल होगा। वास्तव में, याचिकाकर्ता अब जो मांग कर रहे हैं, उसे राज्य द्वारा ऊपरी आयु सीमा में एक बार की छूट प्रदान करके नियम 4 के रूप में देने की मांग की गई थी। हालांकि, उस नियम को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया गया है| इन रिट याचिकाओं में दावा की गई राहत देना उच्च न्यायालय के फैसले को नकारने के बराबर होगा, हालांकि W.P. (C) संख्या 2010 का 59 यह अंतिम हो गया है| इसके अलावा, वर्ष 2003 में भर्तियां की गईं, जिसमें ऐसे कई शिक्षकों ने भाग लिया। पिछले 10 सालों से, प्रतिवादी प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति कर रहा है और यह याचिकाकर्ताओं का मामला नहीं है कि अप्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति नियमों का सावधानीपूर्वक पालन करके नियुक्ति की जाती है। इन रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय में मुकदमेबाजी के दो दौर से संबंधित तथ्यों का खुलासा भी नहीं किया, जो दिनांक 29.9.2003 (के रूप में रिपोर्ट किया गया) के निर्णय में समाप्त हुआ **2003 (1) जेएलजेआर 322**). वर्ष 2008 में आयोजित दूसरी भर्ती प्रक्रिया के बाद ही, वर्तमान रिट याचिकाएं वर्ष 2010 या उसके बाद दायर की गईं।

21. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ताओं को अपने मामले की तुलना बिहार में अपने समकक्षों से करने की अनुमति नहीं होगी। जहां तक बिहार राज्य में समकक्षों का संबंध है, उन्होंने समय पर रिट याचिकाएं दायर की थीं, यानी वर्ष 2003 में पटना उच्च न्यायालय में, जिसमें वे व्यक्ति सफल हुए थे। पटना उच्च न्यायालय ने उन रिट याचिकाओं को दिनांक 1.7.2004 के फैसले के माध्यम से अनुमति दी, जिसमें बिहार राज्य को *राम विनय कुमार का* केस के फैसले को लागू करने का निर्देश दिया गया था। । ऐसी परिस्थितियों में यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर इन याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं को कोई राहत देने के लिए इच्छुक नहीं होगा, खासकर जब ऐसा होता है पाया गया कि प्रतिवादी/झारखंड राज्य ने संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए वैधानिक भर्ती नियमों के अनुरूप कदम उठाए हैं।

22. इन रिट याचिकाओं में कोई गुण नहीं पाए जाने पर, उन्हें खारिज कर दिया जाता है। सभी लंबित अंतर्वर्ती आवेदन को भी बर्खास्त किया जाता है।

. जे.
[सुरिंदर सिंह निज्जर]

. जे.
[ए. के. सीकरी]

नई दिल्ली 25
फरवरी, 2014

<u>यह अनुवाद पीयूष आनन्द, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया है।</u>